C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XX, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 5, Tuesday, November 22, 2016/Agrahayana 01, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 and 82	8-26
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 83 to 100	27-113
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	114-761

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 763-767

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
51st to 59th Reports 768-769

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
10th to 12th Reports 770

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
276th to 279th Reports 770-771

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to conserve and declare Buxar – "Tapo Bhoomi" of Rishi Vishwamitra – as well as other religious, historical and mythological places in Bihar as a National heritage

Shri Ashwini Kumar Choubey 777-779

(ii) Need to start cow sanctuaries in the country

Shri Prahlad Singh Patel 780

(iii) Need to provide Rajasthan its allocated share of Satluj River water and also appoint a member from Rajasthan in Bhakra Beas Management Board

Shri Nihal Chand 781

(iv) Need to appoint adequate number of dental hygienists in proportion to the population of the country and also permit them to contest elections in Dental Council of India and State Dental Councils

Shri Kaushal Kishore 782

(v) Need to construct Railway over bridges in Mehsana city, Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel 783

(vi) Need to construct roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in all the villages of Bhilwara Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Subhash Chandra Baheria 784

(vii) Need to conduct certificate course in manufacturing in Industrial Training Institutes in the country

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 785

(viii) Need to undertake renovation of historic Surya Temple and other temples in Aurangabad Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Sushil Kumar Singh 786

(ix) Need to address the problems faced by retired bank employees

Shri Raghav Lakhanpal 787

(x) Need to reduce the train fare for daily commuters in super fast mail/express trains

Shri D. S. Rathod 788

(xi) Need to augment railway services in Barmer parliamentary constituency, Rajasthan

Col. Sona Ram Choudhary 789

(xii) Need to set up AIIMS like Institute in Kozhikode district of Kerala

Prof. Richard Hay 790

(xiii) Need to construct an underpass near railway crossing no. 201 in Karauli district, Rajasthan

Dr. Manoj Rajoria 791

(xiv) Need to take adequate measures for all round development of Sagar district, Madhya Pradesh

Shri Laxmi Narayan Yadav 792

(xv) Need to extend Chitrakootdham - Kanpur Intercity Express upto Lucknow

Shri Bhairon Prasad Mishra 793

(xvi) Need to decongest the National Highway Nos. 66 and 766 at Calicut in Kerala

Shri M. K. Raghavan 794

(xvii) Regarding denial of visa by China to sportspersons from Arunachal Pradesh

Shri Ninong Ering 795

(xviii) Regarding widening of National Highway No. 181 between Mettupalayam and Wayanad

Shri P. Nagarajan 796

(xix) Need to provide stoppage of Yercaud Express train at Cauvery Railway station running between Chennai Central and Erode Junction in Tamil Nadu

Shri S. Selvakumara Chinnaiyan 797

(xx) Regarding alleged fraud in implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

Shri Sultan Ahmed 798

(xxi) Need to promote organic farming in Arambagh Parliamentary Constituency in West Bengal

Shrimati Aparupa Poddar 799

(xxii) Need to ensure affordable cancer drugs in India

Shri Rabindra Kumar Jena 800

(xxiii) Need to include 'Pravara Nilwande' project in Shirdi parliamenary constituency, Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana and also allocate adequate funds for the purpose

Shri Sadashiv Lokhande 801

(xxiv) Need to include Srikakulam in Andhra Pradesh in the list of smart cities

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 802

(xxv) Need to compensate Telangana for losses due to heavy rains during September, 2016

Shri B. Vinod Kumar 803

(xxvi) Need to set up Ekalavya Model Residential Schools in remaining four districts of Tripura

Shri Jitendra Chaudhury 804

(xxvii) Need to include crop loss due to spurious seed varieties and damage caused by wild animals in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Shri Dushyant Chautala 805

(xxviii) Need to release relief fund to Bihar for rehabilitation of people distressed due to loss of life and property caused by floods in the State

Shri Kaushalendra Kumar 806

(xxix) Need to provide reservation to Maratha community

Shri Raju Shetty 807

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 809

Member-wise Index to Unstarred Questions 810-816

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 817

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 818

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, November 22, 2016/Agrahayana 01, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

22.11.2016

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नम्बर - 81, श्रीमती रमा देवी जी।

(Q. 81)

...(व्यवधान)

11.02hours

(At this stage S/Shri Kalyan Banerjee, K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

श्रीमती रमा देवी: महोदया, पड़ोसी देश पाकिस्तान आज हम से इतना पीछे है कि वह हमारा सामना किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकता है।...(व्यवधान) परन्तु, घटिया तरीके से घुसपैठ करवा कर, ड्रग्स भेज कर, नकली नोट भिजवाकर, आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेनाओं पर आक्रमण करवा कर पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैला रहा है।...(व्यवधान) राज्य सरकार कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को वी.वी.आई.पी. ट्रीटमेंट देती है तथा उनके ऐशो-आराम, जैसे उनके देश-विदेश के दौरे के लिए व कश्मीर के बाहर जाने पर टिकट, होटल एवं सवारी की सुविधा तथा सुरक्षा भी देती है।...(व्यवधान) उनकी सुरक्षा इत्यादि पर सालाना लगभग 100 करोड़ रू. खर्च होते हैं। ...(व्यवधान) उसका 90 प्रतिशत हिस्सा हमारे केन्द्र से तो नहीं जाता है, परन्तु इसके बावजूद कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा समय-समय पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की जाती है और पाकिस्तान के झंडे लहराये जाते हैं। ...(व्यवधान) वे कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की नीतियों एवं बैठकों का बहिष्कार करते हैं।...(व्यवधान) अलगाववादियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के स्कूलों को जलाया जाता है।...(व्यवधान) उन्होंने कई स्कूलों को जला दिया, जहां गरीब एवं मध्यम वर्ग के कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं। ...(व्यवधान) वे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी एवं हिंसक घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों और उन्हें सहायता करने वाले तत्वों को चिन्हित करने एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वे क्या सोच रखते हैंi ...(व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अधिकार छोड़ कर बैठ जाना ठीक काम नहीं है, निःस्वार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या जी ने सही कहा है कि समय-समय पर पाकिस्तान और सीमा के उस पार से जो गतिविधियां होती हैं, उनसे प्रभावित हो कर, जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं, जिससे वहां का शांतिपूर्ण वातावरण खराब हो।...(व्यवधान) इसलिए गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार के साथ मिल कर, वहां का जीवन कैसे सामान्य रूप से चले, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी कदम उठाये गये हैं।...(व्यवधान) यह भी सच है कि कुछ सैपरेटिस्ट लोग, जिनको सिक्योरोटी भी दी गई है।...(व्यवधान) साथ-साथ वे कहीं बाहर जाकर कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हैं, जो भारत विरोधी होते हैं।...(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी निजी तौर पर सारे मामले का जायजा लेते रहे हैं और इस वजह से हालात सुधारने में काफी मदद मिली है।...(व्यवधान) आपने देखा होगा कि पत्थर फेंकने की घटना और जो दूसरी घटनाएं भी होती थीं, उनकी संख्या में काफी कमी आई है।...(व्यवधान) हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर जम्मू-कश्मीर के हालात को जल्द सुधारेंगे।...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : महोदया, माननीय मंत्री जी के जवाब से सबसे ज्यादा संतुष्टि इस बात की हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काले धन के लिए नोटबंदी का जो फैसला लिया है, उससे आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग्स माफिया को होने वाली फंडिंग पर रोक लगी है तथा स्कूलों में आगजनी भी बंद हुई है।...(व्यवधान) इससे स्पष्ट होता है कि भारत विरोधी लोगों को पत्थरबाजी करने के लिए पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों से सहायता मिलती थी।...(व्यवधान) आज यह सहायता भारत विरोधी लोगों को नहीं मिल रही है, इसलिए वे शांत हो गए हैं। इस बात का हमें बहुत संतोष हो रहा है।...(व्यवधान) मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देना चाहती हूं कि आपने इस तरह के जो निर्णय लिए हैं, उनसे लोगों में बहुत संतोष है तथा इन लोगों में जो असंतोष है, उसे पूरा देश देख रहा है।...(व्यवधान) इनके अपने जीने के फेर में ये सारी कहानी हो रही है।...(व्यवधान) हमने मुआयना किया है और जो लोग चार-पांच घंटे लाइन में लगे होते हैं, वे भी संतुष्ट हैं कि जो हो रहा है, वह बहुत अच्छा हो रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, सदन में जो अशांति का वातावरण बनाया जा रहा है, उसे सारा देश देख रहा है और इन लोगों को सबक भी सिखाएगा।...(व्यवधान) इस बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूं -

"तुम्हें वफा याद नहीं, मुझे जफा याद नहीं,
जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं,

तुम्हें वफा याद नहीं तो मुझे जफा भी याद नहीं। ''

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, माननीय सदस्या का कहना बिलकुल सही है कि प्रधानमंत्री जी ने 8 नवम्बर, 2016 को हाई करेंसी नोट्स के विमुद्रीकरण की जो घोषणा की है, उसका सबसे जोरदार असर यह हुआ है कि सरहद पार से जो फेक करेंसी नोट्स सप्लाई होते थे, वह लगभग बंद हो गये हैं।...(व्यवधान) 8 नवम्बर के बाद से अभी तक पाकिस्तान बार्डर से इस तरह की कोई घटना की खबर नहीं आई है, जिसमें कि लोगों को पांच सौ और हजार रुपए के नोट देकर पत्थरबाजी कराते थे। इस तरह की घटनाएं बंद हो गई हैं तथा नोटबंदी से और भी फायदे हुए हैं।...(व्यवधान) विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है, इसलिए मैं अभी ज्यादा बता नहीं सकता हूं, लेकिन टैरर फंडिंग में नोटबंदी का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है।...(व्यवधान)

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा : अध्यक्ष महोदया, सरकार ने जवाब दिया है कि सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाती है।...(व्यवधान) इस मामले में हम राज्य सरकार पर कितना भरोसा करते हैंi...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राज्य सरकारें ठीक तरह से समीक्षा नहीं कर पाती हैं, उन पर भारत सरकार क्या देख-रेख रखती हैंi...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि किसी भी राज्य के लॉ एंड आर्डर की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होती है और आंतरिक सुरक्षा की पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है।...(व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में जो हालत है, उसे ठीक करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, अन्यथा हम इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए समय-समय पर सुरक्षा जायजा लिया जाता है कि किसको किस श्रेणी में सिक्योरिटी दी जाए, यह सेन्ट्रल एजेंसीस और स्टेट मिलकर तय करते हैं।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं...(व्यवधान) और आज के दिन जम्मू-कश्मीर सरकार और केन्द्र सरकार तालमेल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है।...(व्यवधान)

श्री थुपस्तान छेवांग: अध्यक्ष महोदया, ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां जम्मू-कश्मीर के एक ही भाग कश्मीर घाटी में होती हैं।...(व्यवधान) इसका असर लद्दाख में बिलकुल नहीं है और जम्मू के केवल कुछ ही क्षेत्रों में इसका असर है।...(व्यवधान) चिंता की बात यह है कि जितनी डेवलपमेंटल एक्टीविटीज़ हैं, उनका असर जम्मू-कश्मीर के दूसरे भागों पर भी होता है और जो धन आवंटित होता है...(व्यवधान) उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है,...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो धन कश्मीर वादी में काम न करने की वजह से खर्च नहीं हो पाता है...(व्यवधान) क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि उस धन को जहां शांति है और जहां काम ठीक ढंग से चल रहा है, वहां खर्च किया जा सकेंi...(व्यवधान)

दूसरी चिंता यह है, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जितने भी आतंकवादी हैं, उनकी सांठ-गांठ हमारे दुश्मन देशों के साथ है।...(व्यवधान) यह अभी तक केवल कश्मीर वादी तक सीमित है, लेकिन डर यह है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है...(व्यवधान) जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जो आतंकवादी नेता हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है,...(व्यवधान) उनको सुरक्षा दी जाती है और उनको हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध करवायी जाती है,...(व्यवधान) कहीं यह रियासत के दूसरे हिस्सों तक न फैल जाए तो क्या सरकार ने इसका कोई असैसमेंट किया है और इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैंi...(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि कश्मीर में जिस भी सैपरिस्ट लीडर को सिक्योरिटी दी जाती है...(व्यवधान) उसका प्रावधान और प्रोविजन राज्य सरकार करती है।...(व्यवधान) वह हमें इस बारे में जानकारी जरूर देते हैं...(व्यवधान) लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी दी जाती है, वह राज्य सरकार मुहैया कराती है।...(व्यवधान) दूसरा, ऐसा नहीं है कि सुरक्षा देने के बावजूद वह हिन्दुस्तान के विरुद्ध काम करते रहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा बिलकुल नहीं है।...(व्यवधान) जो सैपरिस्ट लीडर्स हैं, उनसे जुड़े हुए काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।...(व्यवधान) बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोग बाहर भी हैं, इस बारे में डिटेल अभी मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन यदि कोई किसी भी राज्य में देश विरोधी कार्रवाई करता है,...(व्यवधान) तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान)

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने सही कहा कि वहां आतंकवाद की समस्या केवल कश्मीर घाटी में है।...(व्यवधान) जम्मू में सामान्य रूप से जिंदगी चल रही है और लद्दाख हिन्दुस्तान की सबसे शांतिप्रिय जगहों में से एक है। लद्दाख में इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।...(व्यवधान) अभी हाल ही में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ था।...(व्यवधान) वहां के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और वहां के काफी लोगों से लद्दाख में मुलाकात की थी...(व्यवधान) और सभी को आश्वस्त किया कि कश्मीर

घाटी में समस्या हो, लेकिन उसका असर लद्दाख क्षेत्र में नहीं होना चाहिए और लद्दाख को सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी, दी जाएगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात ठीक नहीं है। मैं इस तरफ खड़े लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन आप इस तरफ आ जाइए। आप सब को टीवी पर दिखाएंगे, लेकिन आप लोग मंत्री जी को डिस्टर्ब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You cannot disturb the Minister.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या आपका रिप्लाई हो गया हैi

…(व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, यह वाला हो गया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, this is not proper.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want to discuss, you can discuss. आप लोग चर्चा में भाग लीजिए और लोगों की तकलीफ सरकार के सामने रखिए। मगर यह तरीका सही नहीं है। This is not fair.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोगों को शोर करना है तो करते रहिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह लोगों की तकलीफ रखने का तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, आप चर्चा कर सकते हो, आपको चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। प्लीज, आप अपनी सीटों पर जाइये।

…(व्यवधान)

(Q. 82)

श्री हुकुम सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न देश के किसानों से संबंधित है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, लेकिन यह जानकर दुख होता है कि हमारी कृषि पैदावार विश्व के औसत से भी कम आ रही है, यह दुख की बात है। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कई देशों का विवरण दिया है, जिसमें चीन भी शामिल है और यूरोप के देश भी शामिल हैं। हमारी पैदावार उनसे भी कम आ रही है। इसका जो कारण माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया है, मैं उससे सहमत होते हुए कुछ दूसरे कारण भी बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि जो कारण मैं बता रहा हूं, आप उनका भी संज्ञान लेने की कृपा करें, ताकि कुछ सुधार हो सके। ...(व्यवधान) कृषि उत्पादन में कमी की मुख्य बात यह है कि हमारे यहां छोटी जोतें हैं और औसत जोत बहुत कम है, उसके लिए अभी तक हम कोई भी ऐसी मशीनरी किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं कि वे समय के अंदर जुताई कर लें और समय के अंदर बुवाई भी कर लें। ये दोनों बातें बहुत जरूरी थीं और इनके ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।...(व्यवधान)

दूसरी बात कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने पैसों से अपने आधार पर मशीन खरीद सके। अनुदान की व्यवस्था और ज्यादा प्रभावी नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर आ जाए तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : महोदया, माननीय सदस्य किसान की चिंता कर रहे हैं, किसान का सवाल आया है, उस पर इनकी चिंता जायज है।...(व्यवधान) इन्हें मेरे उत्तर को सुनना चाहिए और किसान से संबंधित प्रश्नों में भाग लेना चाहिए। ये तथाकथित किसान हैं, फिर भी इन्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए कि जो वैश्विक औसत उत्पादन है, उससे हमारे देश का औसत कम है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि विदेशों में एक वर्ष में एक फसल लेते हैं और हमारे यहां अधिकतर फसलें एक वर्ष में दो बार लेते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन अगर उस तुलना की दृष्टि से पर डे उत्पादन देखें तो वह लगभग विश्व के उत्पादन के बराबर ही है। ...(व्यवधान) उसका कारण यह है कि वे साल में एक फसल लेते हैं और हम दो फसलें लेते हैं। लेकिन हमारे देश में दो फसलों के कारण जो पर डे उत्पादन है, वह विश्व के उत्पादन के लगभग बराबर है। ...(व्यवधान)

जहां तक प्रयासों का सवाल है, कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए राज्यों को पैसे दिये जा रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद इस पर एक कृषि यंत्रीकरण की योजना चली है और हम राज्यों को कस्टम हायरिंग सैंटर के लिए राशि दे रहे हैं,...(व्यवधान) ताकि छोटे किसान, मझोले किसान उसे किराये पर लेकर अपनी खेती करें। ...(व्यवधान)

जहां तक अन्य प्रश्नों का सवाल है, हम बताना चाहेंगे कि 2014-15 में 12 प्रतिशत कम बारिश हुई थी और 2015-16 में 14 प्रतिशत कम बारिश हुई थी। ...(व्यवधान) बावजूद इसके उत्पादन पर इतना असर इसलिए नहीं पड़ा, क्योंकि देश में जो लगभग 445 क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटी हैं, उन्हें सरकार ने

रिलीज किया था, जिसकी वजह से विपरीत परिस्थिति के कारण भी उत्पादन पर जितना असर पड़ना चाहिए, उतना असर नहीं पड़ा।

माननीय अध्यक्ष : मुझे बहुत दुख होता है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप वास्तव में अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनता के सुख-दुख की चर्चा करनी चाहिए।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.21 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

22.11.2016

12.00 hours

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

*(*Hon. Speaker *in the Chair)*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कमल नाथ, सुदीप बन्दोपाध्याय, के.सी.वेणुगोपाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.एन. रामचन्द्रन, राजेश रंजन, प्रो0 सौगत राय, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, सर्वश्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जय प्रकाश नारायण यादव, एन.के. प्रेमचन्द्रन, धर्मेन्द्र यादव, डॉ. ए. सम्पत, सर्वश्री एंटो एंटोनी, मो0 सलीम, मो0 बदरूद्दोजा खान, पी. करूणाकरन, जितेन्द्र चौधरी और श्री कोडिकुन्नील सुरेश से विभिन्न विषयों पर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय(कोलकाता उत्तर) : मैडम, कुछ तो बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

22.11.2016

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

…(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) विधिक माप-विज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2016 जो 9 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0सा0का0नि0875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) विधिक माप-विज्ञान (पैकेजबंद सामग्री) (संशोधन) नियम, 2016 जो 7 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0सा0का0नि0858(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5345/16/16]

...(व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): महोदया, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं0सा0का0नि0433(अ) जो 21 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (चेयरमैन की अर्हताएं तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2015 का निरसन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 5346/16/16]

...(व्यवधान)

22.11.2016

12.02 hours

(At this stage S/Shri Sultan Ahmed, Kanti Lal Bhuria, Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Parshottam Rupala

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Assam Rifles Para-Medical Staff (Pharmacist, Group 'C' Combatised post, Recruitment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 125 in weekly Gazette of India dated 16th July, 2016 under Section 167 of the Assam Rifles Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 5350/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992:-

(i) The Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 817(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016.

(ii) The Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 818(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016.

(iii) The Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'B' and 'C' posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 819(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016.

(iv) The Indo-Tibetan Border Police Force, Inspector(Librarian), Group 'B' and 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 820(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5351/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Instrumentation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5352/16/16]

(2) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Electronics and Instruments Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5353/16/16]

(3) Memorandum of Understanding between the Engineering Projects (India) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5354/16/16]

(4) Memorandum of Understanding between the Bridge and Roof Company (I) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5355/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 28 of 2016)(Department of Revenue-Direct Taxes)-Allowance of deduction to assesses engaged in infrastructure development for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 5356/16/16]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 29 of 2016)-Communications and IT Sector for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 5357/16/16]

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the first quarter of financial year 2016-2017, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 5358/16/16]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2015-2016.

(2) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Dibrugarh, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5359/16/16]

… (*Interruptions*)

———————

22.11.2016

12.02 ½ hours

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
51st to 59th Reports

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2016-17):-

(1) 51st Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-first Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Role and Functioning of Indian Coast Guard'.

(2) 52nd Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twenty-second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Procurement of Allopathic Drugs in CGHS'.

(3) 53rd Report on the subject 'Land Management in Bharat Sanchar Nigam Limited' based on Para 5.1 of the C&AG Report No. 17 of 2014.

(4) 54th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Railways Finances.

(5) 55th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Civil Engineering Workshops in Indian Railways, Delay in Building the New Rail Bridge over River Sone and Signal and Telecommunications'.

(6) 56th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their First Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Non-compliance by Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of C&AG of India'.

(7) 57th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Eighteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)'.

(8) 58th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Twentieth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Non-compliance by Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of C&AG of India'.

(9) 59th Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Thirty-Second Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Indigenous Construction of Indian Naval Warships'.

… (*Interruptions*)

12.03 hours

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
10th to 12th Reports

DR. SATYA PAL SINGH (BAGHPAT): Madam, I beg to present the Tenth, Eleventh and Twelfth Reports* (Hindi and English versions) of the Joint Committee on Offices of Profit.

… (*Interruptions*)

12.04 hours

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
276th to 279th REPORT

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 274वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 276वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 273वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 277वां प्रतिवेदन।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 275वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 278वां प्रतिवेदन।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्यम विभाग) से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उपबंधों की समीक्षा के बारे में समिति के 272वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 279वां प्रतिवेदन।

… (*Interruptions*)

12.04 ½ hours

---

* **These Reports were presented to Hon'ble Speaker on 14 October, 2016 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Reports under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.**

PAPERS LAID ON THE TABLE ...Contd.

HON. SPEAKER: Item No. 4, Shri S. S. Ahluwalia.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Parshottam Rupala, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956—

(i) Review by the Government of the working of the Bihar State Agro Industires Development Corporation Limited, Patna, for the year 1989-1990 to 1991-1992.

[Placed in Library, See No. LT 5347/16/16]

(ii) Annual Report of the Bihar State Agro Industries Development Corporation Limited, Patna, for the years 1989-1990 to 1991-1992, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5348/16/16]

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5349/16/16]

… (*Interruptions*)

———————

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I will allow you. First, you go back to your seats. I am allowing all of you in the 'Zero Hour'. You can say whatever you want to. But please go back to your seats first.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Ananthkumarji.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam Speaker, through you, I want to make an appeal to all these hon. Members. They should go back to their seats.

मैं सबसे निवेदन करूँगा कि भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हर पहलू पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे विपक्ष के लोग काले धन के पक्ष में हैं, हमारे विपक्ष के लोग आतंकवाद के पक्ष में हैं, जाली नोट के पक्ष में हैं। पूरे देश की जनता मोदी सरकार की इस पहल के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। ...(व्यवधान) हाउस का और बाहर का सेन्स काले धन को मिटाने के बारे में है, इसके खिलाफ संघर्ष करने के बारे में है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि प्रश्न काल मैम्बर्स का राइट होता है। ज़ीरो आवर मैम्बर्स का राइट होता है। प्रश्न काल और ज़ीरो आवर आपका राइट है। इसको आप चलाइए। ...(व्यवधान) हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अभी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) आप जब हुक्म करेंगे, तब से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) पूरी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप बोलिये।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान) हम भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन हम यह चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहें, हमारी बात सुनें और हमने जो एडजर्नमैंट मोशन मूव किया है, उसको आप एडमिट कीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमैंट मोशन पर तो निर्णय हो गया है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा, एक ही लफ्ज़ आपके बारे में बोलूँगा।

"लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती,
बस एक माँ है जो मुझसे खफ़ा नहीं होती।"

इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। ...(व्यवधान) हम एडजर्नमैंट मोशन चाहते हैं क्योंकि सारे देश में गरीब लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, अन-आर्गनाइज्ड मज़दूर मर रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स को मज़दूरी नहीं मिल रही है, बीड़ी वर्कर्स और इतने लोग तबाह और तंग हैं। ...(व्यवधान) प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए, उनको प्रैज़ेंट रहना चाहिए, हमारी बात को सुनना चाहिए। ...(व्यवधान) आप अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़ा अन्याय देश के ऊपर होगा, देश की जनता के ऊपर होगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे एडजर्नमैंट मोशन को आप लीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, माँ भी यह चाहती है कि सब बच्चे मिल-जुलकर रहें, मिल-जुलकर चर्चा करें। माँ यही चाहती है। I am requesting you.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Sudip ji.

… (Interruptions)

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, मैं खड़गे जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ बहुत साफ है। जनता ने मध्य प्रदेश के शहडोल में और असम में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, नरेन्द्र मोदी को जिताया और जनादेश दे दिया कि हम कालेधन के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम स्वच्छ भारत अभियान के साथ हैं, यह बता दिया है। ...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, the submission of the Trinamul Congress is this… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry, सुदीप जी, एक मिनट बैठिये। आप मेरी भी बात समझ लें। मैं हर पार्टी की बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से हल्ला भी करो और हर पार्टी का नेता भी बोले।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am ready to listen all of you.

Yes, please.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam, what I am telling is that from the Chair of the Speaker, being the custodian of this House, you take a firm decision that this matter is to be discussed. What is the harm if it is discussed under Adjournment Motion? We cannot understand. What is the harm in it? Why is the Government not coming forward? If there is a turmoil situation, which is prevailing in the House, the Ruling party is responsible for it. It is not that the Opposition parties are responsible for it.

We are asking for a positive debate. We want to place our observations.

HON. SPEAKER: The Chair is also ready to have a debate but not under the Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: We want to see the hon. Prime Minister being present in the House. Let us make our observations… (*Interruptions*) Why are you not rising to the occasion? You rise to the occasion… (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, we are ready for the debate.… (*Interruptions*) I want to tell the Trinamul Congress leader and my friend, Shri Sudipji that the *Bharat Sarkar*, that is, the Government of India is ready for a debate… (*Interruptions*)

We are ready for a debate in this House; we are ready for a debate in the other House; and we are ready for a debate outside also. But they are not coming out for having a constructive debate… (*Interruptions*)

At this moment itself, Madam Speaker, we are ready for a debate. I do not know why they are running away from a debate… (*Interruptions*)

At both the places, namely, in Sagar, Madhya Pradesh and in Assam, the Bharatiya Janata Party has won under the leadership of Shri Narendra Modi. What is the signal? … (*Interruptions*) The signal to the country is that 'the people of India are with Shri Narendra Modi and the people of India are with this crusade against corruption. That is the message going in the entire country… (*Interruptions*)

Madam, we are ready for a debate. Let them go back to their seats. I am again requesting them to cooperate… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Dr. Venugopalji, what do you want to say?

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you are in the Well. This is not the way. I am sorry.

… (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, we have also given a notice in this regard about "the sufferings of the common people due to the shortage of new Rs.500 and lower domination currencies, and overcrowding at banks and ATMs in the country after the demonetization announcement by the Government."

On this matter, we want a discussion and we have already given a notice of Adjournment Motion on it… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. It will not go like this.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You do not want a discussion!

… (*Interruptions*)

12.14 hours

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be treated as laid on the Table of the House. Members may personally handover their matter to the Table as per the procedure.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

22.11.2016

(i) Need to conserve and declare "Buxar-Tapo Bhoomi" of Rishi Vishwamitra-as well as other religious, historical and mythological places in Bihar as a national heritage.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र के पौराणिक महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर सहित बिहार के विश्व सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहलगांव, भागलपुर, बांका जिला अंतर्गत ''मंदार पर्वत'' (जहॉ देवताओं द्वारा शेषनाग को रस्सी के रूप में मंदार पर्वत से लपेटकर पर्वत को मथनी के रूप में प्रयुक्त करते हुए देवासुर संग्राम के दौरान समुद्र मंथन किया गया था), मधुसूदन मंदिर, अंगराज दानवीर कर्ण की धरती नाथनगर, भागलपुर, कर्णगढ़ एवं मुंगेर का कर्णकिला तथा 14वीं सदी के मैथिली कवि कोकिल महान् राष्ट्र कवि विद्यापति जी की पावन जन्म स्थली विस्फी, मधुबनी (मिथिलांचल) सहित ''उगना महोदव'' आदि गौरवशाली स्थलों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर के रूप में घोषित कर उसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं।

बक्सर का ''पंचकोशी मेला'', जहॉ भगवान राम स्वयं उन पॉचों स्थलों पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, उनकी भव्य प्रतिमा एवं राम दरबार की झॉकी स्थापित करने के साथ ही पंचकोशी क्षेत्र को विकसित करने हेतु अवशेषों का जीर्णोद्धार तथा सड़क, पेयजल, विद्युत, विधि-कानून की समुचित व्यवस्था, पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण, पौराणिक तालाब-घाटों आदि को अतिक्रमण मुक्त कर जीर्णोद्धार/निर्माण कराना लोकहित में आवश्यक है। लाखों लोग प्रतिवर्ष तीर्थाटन हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर से पंचकोशी मेले में आते हैं। बक्सर स्थित रामरेखा घाट पर भगवान राम ने बाल्यकाल में गंगा स्नान कर मृतिका से शिवलिंग की स्थापना कर लोक-कल्याणार्थ पूजा-अर्चना की थी, जो रामेश्वर मंदिर के रूप में सुविख्यादित है। शास्त्रों में वर्णित ''वामन भगवान'' की अवतार भूमि भी यही स्थल रही है, जो आज केन्द्रीय कारा, बक्सर के अंदर है, उसे कारा से मुक्त कर वहॉ सर्वसुलभ दर्शनार्थ भव्य मंदिर निर्माण करने, सप्तपौराणिक शिवकुण्ड स्थल (प्राचीन गौरीशंकर मंदिर) तथा भगवान राम के चरण-रज द्वारा शिला रूप से माता अहिल्या का उद्धार स्थल अहिरौली आदि क्षेत्रों के जीर्णोद्धार सहित परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराया जाए। बक्सर मर्यादा पुरूषोत्तम राम की शिक्षा-दीक्षा (प्रशिक्षण) भूमि के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहॉ चरित्र वन में भगवान राम ने विश्वामित्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर ताड़िकासुर का वध किया था।

अतएव, बक्सर को विश्व पौराणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय धरोहर के मानचित्र पर स्थापित किया जाए।

अतएव केन्द्र सरकार द्वारा विश्व प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित कर दर्जा प्रदान करने एवं राष्ट्रीय, सांस्कृतिक धरोहर की सूची में दर्ज किया जाए। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा घोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कहलगांव, भागलपुर

(बिहार) में यथाशीघ्र शिविर (कैम्प) स्थापित किया जाए, जिससे वहॉ पठन-पाठन प्रारम्भ किया जा सके। इसके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अवशेष खुदाई पूर्ण की जाए तथा विक्रमशिला को बौद्ध परिपथ (बुद्ध सर्किट) के साथ जोड़ा जाए।

अंगराज दानवीर कर्ण की धरती नाथनगर, भागलपुर के कर्णगढ़ एवं मुंगेर के कर्णकिला को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दर्ज करते हुए विकसित कर ''कर्ण स्तूप'' का निर्माण किया जाए।

अतएव विद्यापति जी की जन्मस्थली विस्फी, मधुबनी सहित ''उगना महादेव'' (भगवान शंकर, जो स्वयं उगना बनकर सेवक के रूप में विद्यापति जी के यहॉ चाकरी करते थे) को राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक धरोहर के रूप में घोषित करते हुए विकसित किया जाए। साथ ही 14वीं सदी के महान राष्ट्रकवि विद्यापति जी को महिमामण्डित करते हुए संसद भवन परिसर एवं बिहार विधानमंडल परिसर में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए।

22.11.2016

(ii) Need to start cow sancturies in the country.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : देश की खेती में बैलों का उपयोग कम होने के कारण बड़ी संख्या में बछड़े, बैल एवं गाय सड़कों पर जमा हो रहे हैं, जिससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा है तथा सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं। खड़ी फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान होने के कारण देश का किसान संयम खो रहा है। मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध के कारण कसाई बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं। बंजर भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने का एकमात्र विकल्प एवं उपाय देशी गाय का गोबर ही है। देशी गौवंश अमूल्य धन है लेकिन सरकारों की दिशाहीन नीतियों के कारण संरक्षक किसान गौवंश के प्रति उदासीन होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश की भविष्य की कृषि, किसान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। गौवंश के लिए भूसा, चारा, पानी चिकित्सा एवं मृत पशु का संस्कार गंभीर समस्या बन गया है। अतः सरकार को गौवंश के संरक्षण के लिए युद्धस्तर पर गौ अभ्यारण्य प्रारंभ करना चाहिए। प्रयोग स्वरूप दमोह जिले के जारूधाम में समाज एवं सरकार के सहयोग से 107 हैक्टेयर भूमि में गौ अभ्यारण्य प्रारंभ हुआ है।

22.11.2016

(iii) Need to provide Rajasthan its allocated share of Satluj river water and also appoint a member from Rajashtan in Bhakra Beas Management Board.

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तरफ दिलाने का आग्रह करूॅगा। पहला अंतर्राज्यीय जल समझौता 29 जनवरी, 1955 को हुआ और राजस्थान प्रदेश को अपने हिस्से का पानी 8 एम.ए.एफ. मिलन तय हुआ। हरियाणा व पंजाब राज्यों के बनने के बाद पंजाब से राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 13 जनवरी, 1959 को राजस्थान व पंजाब के बीच सतलुज नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ, फिर भी राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गॉधी की अध्यक्षता में राजस्थान व पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें सतलुज नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता हुआ। आज भी पंजाब, राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा है। अंतर्राज्जीय जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी आवंटित हुआ था, परंतु पंजाब आज भी 8 एम.ए.एफ. पूरा पानी भी राजस्थान को नहीं दे रहा है। 24 जून, 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी ने तीनों (राजस्थान, पंजाब व हरियाणा) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान का पूरा पानी (8.6 एम.ए.एफ.) देने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक पूरा पानी नहीं दिया गया।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में मध्यस्थता कर पंजाब से पूरा पानी राजस्थान प्रदेश को दिलवाने में मदद करे एवं आज तक भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब एवं हरियाणा का सदस्य ही नामित हुआ है, राजस्थान से एक बार भी सदस्य नामित नहीं हुआ, जबकि समझौते के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। राजस्थान का सदस्य भी भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में नामित हो, ऐसा केंद्र सरकार से आग्रह करूॅगा।

22.11.2016

(iv) Need to appoint adequate number of dental hygienists in proportion to the population of the country and also permit them to contest elections in Dental Council of India and State Dental Councils.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : मैं सरकार का ध्यान **डेंटल हाईजिनिस्ट**, जिसे **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** कहते हैं, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। संसद द्वारा डेंटिस्ट एक्ट, 1948 के तहत **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का प्रावधान किया गया था, जिससे प्राथमिक स्तर पर लोगों को मुख एवं दाँतों में होने वाली बीमारियों जैसे पायरिया, कीड़ा एवं मुख के कैंसर आदि से बचाया जा सके और लोगों को इसके बारे में दन्त शिक्षा के द्वारा जागरूक किया जा सके। **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को ओरल हाईजीन केयर प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे प्राईवेट हो या सरकारी सेवा, आवश्यक रूप से दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, परंतु **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** को दन्त परिषद में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद न तो वोट देने का अधिकार है, न ही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी** का नामांकन होता है।

इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि भारतीय जनसंख्या के अनुपात में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** को मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए और दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों को भारतीय दन्त परिषद एवं राज्य दन्त परिषदों में सरकार की ओर से **दन्त स्वास्थ्य विज्ञानियों** के प्रतिनिधियों के रूप में नामांकित किया जाए।

22.11.2016

(v) Need to constuct Railway over bridges in Mehsana city, Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : मेहसाणा शहर उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यह मिल्क सिटी, ऑयल सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से भी जाना जाता है।

मेहसाणा शहर के बीचों-बीच रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसमें मेहसाणा दो हिस्सों ईस्ट-वेस्ट में बंट गया है। मेहसाणा 1 और 2 के बीच यातायात के लिए नार्थ में गोपीनाला और साउथ में भमरीया नाला पड़ता है। दोनों नालों से ए.सी. तथा लग्जरी बस तथा भारी वाहनों को आने-जाने में दिक्कत होती है। ए.सी. बसों को 4 किलोमीटर का राउंड लेकर सिटी में से बाहर निकलना पड़ता है। ईस्ट में सभी जिला प्रशासन ऑफिस, नगर इकाई, कार्यालय, स्टेट ट्रांसपोर्ट मुख्यालय, व्यापारी बाजार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज व जिला अस्पताल पड़ते हैं। वहॉ आने-जाने तथा मरीजों के लिए दो आर.ओ.बी. हैं, लेकिन वहॉ पर बहुत ट्रैफिक रहता है। डी.एम.आई.सी. का कार्य आगे बढ़ रहा है। तब उनके निर्माण के साथ-साथ ईस्ट-वेस्ट मेहसाणा को जोड़ने के लिए मैंने पिछले पॉच सालों से और अभी भी मैंने दो आर.ओ.बी. की मॉग की है।

मेहसाणा की जनता की इन वाजिब मॉगों पर गौर किया जाए।

22.11.2016

(vi) Need to construct roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in all the villages of Bhilwara Pariamentary Constituency, Rajasthan.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था। इसमें जनसंख्या को आधार मानकर गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ। आज इसके माध्यम से गांव के विकास में तेजी आई है। इस योजना के तहत 1991 तथा बाद में 2001 की जनगणना को आधार माना गया तथा इस आधार पर स्वीकृतियां हो रही हैं। राजस्थान प्रदेश में 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों में सड़कों के निर्माण का काम पूरा हो गया है, परन्तु ऐसे कुछ राजस्व ग्राम, जो योजना के बनते समय नगरीय क्षेत्रों में थे इसलिए वे इस योजना से नहीं जुड़ सके। परन्तु आज यह राजस्व गांव होकर ग्राम पंचायतों का हिस्सा हैं तथा 2011 की जनगणना के हिसाब से उनकी जनसंख्या 500 से भी ज्यादा है, परन्तु वहां सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की मांगडलगढ़ तहसील के गांव तिरोली ग्राम पंचायत होड़ा का उदाहरण है। यह गांव पहले नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा था परन्तु अब राजस्व गांव है तथा जनसंख्या भी 500 से अधिक है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में देशव्यापी सर्वे करवा कर ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा जाये, इससे इन गांवों के विकास में तेजी आयेगी।

22.11.2016

(vii) Need to conduct certificate course in manufacturing in Industrial Training Institutes in the country

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से एल.ओ.सी. पार करके आतंकियों के कैम्पों का सफाया किया गया उस कार्य से सेना एवं आम जनता का मनोबल बढ़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश की जनता में स्वतः स्फूर्ति चेतना का संचार हुआ है। जिसके लिए भारत सरकार एवं सेना अभिनंदन के पात्र हैं।

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों में चीन द्वारा जिस प्रकार से भारत के हितों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनदेखी करके भारत के विरूद्ध पाकिस्तान के षडयंत्रों को मान्यता दी जा रही है उस पर रोष व्याप्त है। एक सरकार के नाते विश्व व्यापार संगठन के नियमों के दायरे के कारण जो कार्य सरकार नहीं कर सकती वे कार्य जनता स्वयं कर रही है। आज जनता चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपना रही है।

मेरा सरकार को सुझाव है कि आज इस जन चेतना को सही मार्गदर्शन देते हुए आवश्यकता है कि इसी तर्ज पर जीवन हेतु आवश्यक चीजों को बनाने हेतु छोटे-मोटे गृह उद्योग के लिए युवकों को बड़ी मात्रा में प्रेरित करना चाहिए अन्यथा यह जो चेतना है वह समय जाते फिर से उसी ओर प्रवाहित होगी। सरकार ऐसी छोटी-मोटी चीजों को बनाने हेतु आई.टी.आई. के माध्यम से प्रमाणित कोर्स शुरू करती है। विदेशी चीज़ों के सामने लोगों को मेड इन इंडिया का विकल्प भी मिलेगा। विशेषकर प्लास्टिक मोल्डिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यह प्रयास करने की आवश्यकता है।

22.11.2016

(viii) Need to undertake renovation of historic Surya Temple and other temples in Aurangabad parliamentary constituency, Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड में ईलाकाल में निर्मित एक प्राचीन सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। इस स्थान पर श्रद्धालुओं/तीर्थ यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस पवित्र स्थल पर वर्ष में दो बार छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर करीब 25 लाख श्रद्धालु देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण तीर्थ यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मंदिर के कई शिलालेख खिसक गए है और कई खिसकने के कगार पर हैं। इस मंदिर तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। पेयजल, स्नानागर, शौचालय, यात्री निवासी, सड़क और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, मेरे संसदीय क्षेत्र के गया और औरंगाबाद जिला के कोचेश्वरनाथ मंदिर, बैजुधाम, बांके धाम, केशवधाम, उमगेश्वरी माता मंदिर, गजनाधाम, दुधेश्वरनाथ मंदिर, सत्यचंदी माता मंदिर की स्थिति जर्जर है और इस संबंध में अधोहस्ताक्षरित द्वारा सरकार को तीन माह पूर्व सूचित किया गया है, परंतु अभी तक इस संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की गई है।

मेरा आग्रह है कि जनहित में सूर्य मंदिर देव सहित उपर्युक्त वर्णित मंदिरों के लिए सड़क, पेयजल, स्नानागार, प्रसाधन, यात्री निवास और सफाई की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए इन मंदिरों के मरम्मतीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की जाये। साथ ही साथ इन मंदिरों का उन्नयन विकास और संरक्षण केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा की जाये।

(ix) Need to address the problems faced by retired bank employees

SHRI RAGHAV LAKHANAPAL (SAHARANPUR): I would like to draw the attention of the Government towards bank retirees in the country who have been agitating for the last more than one decade under the banner of All India Bank Retirees Federation (AIBRF) which represents more than 1,55,000 retirees from 44 banks on the following long pending demands/issues:

1.There are about 60,000 surviving retirees who retired before November, 2002 who get dearness allowance at much lower rate since May 2005. About 2,40,000 retirees who retired after Nov. 2002 get dearness allowance at higher rate as per the settlement signed in 2005. This group of retirees strongly feel that this is sheer discrimination. These retirees are at the advancing age and most of them are above 70 years presently.

2. AIBRF have been pleading with IBA/Government to increase dearness allowance at par with the Government sector/RBI to ensure dignified life to the family after death of pensioners.

3. Updation of Basic Pension to past retirees.

4. Pension option to left over retirees.

5. IBA must hold discussion with AIBRF.

Apart from the above, I would like to urge the Government to kindly also favorably consider all other pending issues pertaining to Bank retirees in the country and to take necessary steps to solve their problems.

22.11.2016

(x) Need to reduce the train fare for daily commuters in superfast, mail/express trains.

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) : भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर उन्हें सुपरफास्ट ट्रेनों में परिवर्तित किया गया है। उसके साथ ही इन ट्रेनों का किराया भी बढ़ाया गया है। इस निर्णय की वजह से रोज अपनी नौकरी एवम् रोज़गार के लिए अप-डाउन करने वाले यात्रियों को ऐसी ट्रेनो से यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है और उनके लिए यात्री ट्रेन कम हो गई हैं। भारत सरकार, भारतीय रेलवे की सभी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने जा रही है तब ऐसी गाड़ियों की स्पीड बढ़ने से यात्री किराये में हुई बढ़त/किराया को मूल स्थिति में लाया जाना चाहिए और सभी रेल यात्रियों को मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसी मेरी मंत्रालय से मांग है। ऐसा करने से रेल एवं रेलवे स्टेशनों पर हो रहा ट्रैफिक बहुत कम होगा।

22.11.2016

(xi) Need to augment railway services in Barmer parliamentary constituency, Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मैं बाड़मेर संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) का प्रतिनिधित्व करता हूॅ। यह एक अभावग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्र है। सभी जानते हैं कि मारवाड़ी समूचे हिन्दुस्तान नहीं अपितु विश्व में छाये हुए हैं। परन्तु वे अभी भी सांस्कृतिक परम्पराओं एवं संस्कारों के कारण अपनी जन्मभूमि से जुड़े हैं। आज़ादी के 65 वर्षों पश्चात् कुदरत यहां के लोगों पर मेहरबान हुई है। यहां अब प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा के रूप में तेल, कोयला, लिग्नाइट, स्टील, बेस लाइम, बेटोनाइट, जिप्सम एवं ग्रेनाइट का भंडार मिला है। इसी वजह से यहां भी औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित हो रही हैं। बाड़मेर औद्योगिक रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है एवं जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीमा से सटे होने के कारण एयरफोर्स, आर्मी एवं बी.एस.एफ. के जवानों का आवागमन भी इसी क्षेत्र में होता रहा है। इन सबको ध्यान में रखा जाये तो इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधाएं नाममात्र हैं। दक्षिणी व उत्तरी भारत को रेल सेवाओं से सीधा जोड़ने हेतु बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ा जाये ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। इससे व्यापारियों को माल ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा एवं समय दोनों की बचत होगी। जोधपुर रेलवे मुख्यालय पर जमीन की कमी होने के कारण यहां यात्री रेलगाड़ियों को रोकने, उनकी सफाई एवं मेंटीनेंस करने में परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में बाड़मेर स्टेशन जहां पर्याप्त मात्रा में रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है वहां लोकोशेड एवं पार्किंग का निर्माण करवाया जाये तो कई गाड़ियों को बाड़मेर रोका जा सकता है। इससे दोहरा लाभ होगा एक तो जोधपुर पर लोड नहीं रहेगा एवं बाड़मेर/जैसलमेर की जनता को गाड़ियॉ भी मिल जायेंगी। निम्न गाड़ियों को बाड़मेर तक बढ़ाया जाया तथा बाड़मेर में ही पार्क किया जाये। मण्डोर एक्सप्रेस, सूर्यनगरी एक्सप्रेस, जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस, दिल्ली-सुजानगढ़-भगत की कोठी (14705-06)। निम्न गाड़ियों को जैसलमेर तक बढ़ाया जाये तथा बाड़मेर में ही पार्क किया जाये- दिल्ली-बीकानेर, पुरी-जोधपुर, चैन्नई-जोधपुर। निम्न गाड़ियों के फेरे बढ़ाये जाये- मद्रास-जोधपुर (16125), गुवाहाटी एक्सप्रेस, यशवंतपुरम एक्सप्रेस, जोधपुर से वाया रामदडी मोकलसर, जालौर-अहमदाबाद, जैसलमेर-हावड़ा, जैसलमेर-मुंबई, चैन्नई-अहमदाबाद ''हम सफर'' जो नई संचालित की गयी है, को जोधपुर तक बढ़ाया जाये। जैसलमेर-बाड़मेर-दिल्ली एक्सप्रेस में साधारण कोच की संख्या दिल्ली तक बढ़ाई जाये। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहता हूं कि वाणिज्यिक, सामरिक दृष्टि से उक्त प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो रेलवे एवं आम जन के हित में होगा।

(xii) Need to set up AIIMS like Institute in Kozhikode district of Kerala

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): There is a need for setting up of AIIMS like institute at Calicut, Kerala since North Malabar has been deprived of super specialty medical facilities. The people from five districts are forced to travel upto Thiruvanthapuram situated at the southern part of Kerala to avail better medical treatment. Especially the poor are facing problem due to this long distance travel. Hence, urgent steps may be taken to establish AIIMS like Institute in Kozhikode district of Kerala.

22.11.2016

(xiii) Need to construct an underpass near railway crossing no. 201 in Karauli district, Rajasthan.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर के करौली जिले में हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनने के कारण हिण्डौन महवा फाटक संख्या 201 के बंद होने के कारण आ रही परेशानियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

करौली जिले में हिण्डौन सिटी में रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनने के कारण हिण्डौन महवा फाटक संख्या 201 बंद कर रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। जिसकी तकनीकी गलती के कारण शहर वर्धमान नगर सहित शहर की काफी कॉलोनियों के हज़ारों लोग धारा से अलग हो गए हैं। शहर जाने के लिए 5 कि.मी. का लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है या फिर जान खतरे में डालकर रेलवे लाईन पैदल पार करनी पड़ती है। आपातकाल में मरीजों तथा विद्यार्थियों को स्कल, कॉलेज व अस्पताल आदि जाने में विशेष परेशानी हो रही है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिण्डौन सिटी में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण बन्द किये गये फाटक संख्या 201 के पास जल्द से जल्द अण्डर पास का निर्माण कराया जाये जिससे हिण्डौन शहरवासियों को राहत मिल सके।

22.11.2016

(xiv) Need to take adequate measures for all round development of Sagar district, Madhya Pradesh.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) : नियम 377 के माध्यम से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सागर (मध्य प्रदेश) विकास संबंधी बाहुल्य स्रोत और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक साक्षरता स्तर होने के बाद भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है और औद्योगिक पिछड़े जिलों की 'बी' श्रेणी में है। डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के कारण इस जिले का साक्षरता स्तर 77 प्रतिशत से भी अधिक है और महिलाओं में शिक्षा के प्रति लगाव है। जिन्हें कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल श्रेणी में लाया जा सकता है और इस मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास एवं सेवा कार्यों में समुचित ढंग से किया जा सकता है। यह जिला भारत के बीचो-बीच है। इस जिले में विकास का बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। जिसके लिए सड़कें, सिंचाई एवं सोयाबीन आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाने जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागर जिले को देश के 100 चयनित स्मार्ट सिटी में रखा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास की काफी संभावनाएं हैं इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सागर जिले को पिछड़े जिले से एक विकासशील जिले में परिवर्तन करने के लिए अध्ययन और सर्वे किया जाये।

22.11.2016

(xv) Need to extend Chitrakootdham-Kanpur Intercity Express upto Lucknow.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वप्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन स्थल चित्रकूट धाम से कानपुर तक प्रतिदिन इन्टरसिटी एक्सप्रेस चलती है जो कानपुर में करीब 14 घंटे खड़ी रहती है। वहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ मात्र 1 घंटे की दूरी पर 80 कि.मी. है। इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने हेतु काफी समय से आम नागरिकों की मांग रही है। इसे लखनऊ तक बढ़ाने से यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ रेलवे के राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। अस्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि अतिशीघ्र निर्णय लकर चित्रकूट धाम-कानपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाने की कृपा करें।

(xvi) Need to decongest the National Highway Nos. 66 and 766 at Calicut in Kerala

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Calicut is an emerging city. Two National Highways namely NH-66 and NH-766 pass through this city. One of the oldest known cities, this is a major city connecting Kerala with Karnataka through Mysore as well as Mangalore apart from the hill station of Waynad and other places in the state. The erstwhile mini-byepass at Eranjipalam has now become a bottleneck for road users with vehicle congestion resulting in traffic jams for hours together affecting long distance passengers as well as local movement.

It is, therefore, urged that the Eranjipalam Junction may be provided with a Grade Separator under the Sethubharatham or the Road Safety Scheme. The expected cost is Rs. 35 Crore.

Similarly, the Calicut Byepass with 28 Kms is the only stretch where 45 metre land has been acquired in Kerala. The tender process for four lanning on this byepass should commence immediately.

22.11.2016

(xvii) Regarding denial of visa by China to sportspersons from Arunachal Pradesh

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): I want to highlight the problem about the numerous events when Arunachalee sportspersons have been denied visa by China. It is an act of discrimination against people of Arunachal Pradesh. This has happened to sportspersons of Arunachal Pradesh many times after Chinese aggression of 1962 and due to the territorial dispute between the two nations. China issues the stapled visa to Arunachalee. But India does not recognize stapled visa and therefore does not allow them to travel.

The issue has serious implication as recently, Bamang Tago has not been granted visa while his team left for China. Tago is the secretary of Arunachal State Badminton Association and nominated manager of Indian Badminton Team for Thaihot China Open 2016. Before this, many times sportspersons have been deprived of playing in China due to immigration issues. In 2011, five Karate team members; In January 2012, a team of Arunachal weightlifters; In October 2013, two Archers from Arunachal Pradesh could not participate in China. The problem is of serious concern as China is an emerging prominent place for international sports.

22.11.2016

(xviii) Regarding widening of National Highway No. 181 between Mettupalayam and Wayanad

SHRI P. NAGARAJAN (COIMBATORE): The National Highway No. 181 connecting Mettupalayam and Wayanad via coonoor, Qoty, Gudalur is passing through my Coimbator Parliamentary Constituency in Tamil Nadu. The much-demanded widening of the National Highway 181 stretch between Mettupalayam and Wyanad needs to be expedited by the National Highways Authority of India (NHAI) for the benefit of tourists and common passengers. This is an important stretch of NH 181 through which the vehicles and passengers from both Tamil Nadu and Kerala travel through. The widening and expansion works will help in easy and smooth passing of large number of vehicles through NH 181 and will save the travel time and unnecessary traffic jams due to the narrowness of the road in many places.

Large number of tourists from all over the country who visit the Hill station of Qoty, Coonoor and Mudumalai Wildlife Sanctuary have to use this stretch of NH 181. Due to the present condition for a distance of 172 Km, the time for travel is about 6 hours and the tourists and other common passengers plying on this NH 181 stretch face lots of hardships due to the narrowness of the road in most of the sections.

Therefore, I urge the Union Government to expedite the widening of the NH-181 particularly the stretch between Mettupalayam and Wayanad for the benefit of millions of tourist vehicles and other vehicles passing through this road.

(xix) Need to provide stoppage of Yercaud Express train at Cauvery Railway station running between Chennai Central and Erode Junction in Tamil Nadu

SHRI S. SELVAKUMARA CHINNAIYAN (ERODE): Erode is one of the most important cities in the Kongu Region of Tamil Nadu. The train Yercaud Express (No.22649) runs daily from Chennai Central to Erode Junction and vice versa. Yercaud Express train starts in the night from Chennai and reaches Erode Junction in the morning. As most of the passengers are getting down at Erode Junction, it is flooded with people, both inside and outside the Erode Junction. The heavy vehicular traffic in and around the Junction make the things much worse and people find it difficult to go in and out easily when the Yercaud Express reaches Erode Junction.

In order to reduce this heavy congestion, it is necessary to stop the Yercaud Express Train at Cauvery Railway Station. The passengers belonging to Pallipalayam which is just few Kilometers before the Erode Junction could alight in this stop instead of Erode Junction. this will not only benefit the passengers in and around Pallipalayam area but also reduce the huge traffic jam during the morning hours every day at Erode Junction.

Hence I urge the Hon'ble Union Minister for Railways to take necessary action by providing a stoppage at Cauvery Railway Station for Yercaud Express (Train No. 22649).

22.11.2016

(xx) Regarding alleged fraud in implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

SHRI SULTAN AHMED (ULUBERIA): I would like to draw the attention of the Government to alleged fraud in BANK MITRA Scheme for implementation of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojan (PMJDY) across the country. It has been reported in a leading Newspaper about the role of 'Bank Mitras', who played a vital role in the success of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. As reported several Bank Mitras deposited Rs. 1 (one) into these accounts to push more individuals into opening accounts and keep them active.

While the Government said that the number of zero balance accounts reduced drastically, news reports in September suggested that Rs. 1 (One) was deposited in several accounts to show that these were operational and active. Over 25 crore accounts have been opened under PMJDY and a total deposit of Rs. 44,480 crore have come into these accounts. It is average Rs. 1700 per account.

This type of fraud in banking process give the impression of involvement of the Banks and failure of the monitoring mechanism of the Government. I urge the Government to formulate proper mechanism to prevent this type of fraud.

22.11.2016

(xxi) Need to promote organic farming in Arambagh Parliamentary Constituency in West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Organic agriculture is a production system that sustains the health of soil, eco system and people. Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and good quality of life. The method of farming is studied in the field of agro-ecology.

Haripad, Tarakeshwar, Prushrah, Khanabul part of Dhanakali, Arambagh is very fertile for vegetables. For the upliftment and to educate the farmers there is a need to launch an awareness and training programme to impart technological knowledge and expertise for organic farming in Arambagh Parliamentary Constituency in West Bengal.

(xxii) Need to ensure affordable cancer drugs in India

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): The estimated number of cancer cases in India for 2016 are around 14.5 lakh, which is estimated to go up to 17.2 lakh cases by 2020. It has also been observed that the number of deaths due to cancer in 2016 is estimated to be around 50% of the cases. The survival rate of cancer patients in India when compared to other countries is also poor. amidst this, a recent global study revealed that even though the cancer drugs in India are much cheaper than other developed countries, still the drugs are not affordable. After calculating price as a percentage of wealth adjusted for the cost of living, cancer drugs appear to be least affordable in India and China. Therefore, I urge the Government to intervene in the matter and ensure that cancer drugs are available at affordable prices to all the needy.

22.11.2016

(xxiii) Need to include 'Pravara Nilwande' project in Shirdi Parliamentary constituency, Maharashtra under Pradhan Mantri Krishi Sichayee Yojana and also allocate adequate funds for the purpose

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिर्डी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) के अंतर्गत श्री साईं बाबा का विश्व प्रसिद्ध धाम शिर्डी शहर में स्थित है। जहां पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शनार्थ प्रतिदिन आते हैं। श्री साईं बाबा का समाधि शताब्दी वर्ष, 2018 में है।

शिर्डी में श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं एवं निकटवर्ती गांवों में पानी की परेशानी को दूर किए जाने हेतु अहमदनगर जिले में ''प्रवरा निलवंडे'' केनाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र की ए.आई.बी.पी. योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को व्यय करनी है। लेकिन, अब ए.आई.बी.पी. योजना को बंद कर दिया गया है और इस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है।

राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की ए.आई.बी.पी. योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारम्भ की है, उसके लिए 7 प्रकल्प केन्द्र सरकार को प्रेषित किए हैं जिनमें ''प्रवरा निलवंडे'' प्रकल्प शामिल नहीं है। शिर्डी धाम के निकटवर्ती ग्रामों की भीषण सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ''प्रवरा निलवंडे'' को राज्य सरकार की ओर से आठवें प्रकल्प में केन्द्र सरकार स्वीकार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार से प्रकल्प भिजवाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे वहां के किसानों को न्याय मिल सकें।

राज्य सरकार धनाभाव के कारण अपने हिस्से की राशि देने में असमर्थ है। राज्य सरकार की उक्त 20 प्रतिशत राशि को श्री साईं बाबा संस्थान शिर्डी देने के लिए तैयार है तथा शिर्डी के निकटवर्ती ग्रामों की भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए संस्थान 500 करोड़ रूपए देने को तैयार है। लेकिन, केन्द्र सरकार की ओर से धनराशि का आवंटन न मिलने के कारण इस केनाल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों एवं श्रद्धालुओं को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

22.11.2016

अतः मेरा अनुरोध है कि शिर्डी श्री साईं बाबा की महत्ता और निकटवर्ती ग्रामों की पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो 7 प्रकल्प केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे हैं तथा ''प्रवरा निलवंडे'' प्रकल्प शामिल नहीं है उसको राज्य सरकार केन्द्र सरकार को 8वें प्रकल्प के रूप में प्रेषित करते हुए ''प्रवरा निलवंडे'' केनाल का निर्माण कार्य श्री साईं बाबा के समाधि शताब्दी वर्ष, 2018 के शुभारंभ तक पूरा करवाने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र के किसान अकाल की स्थिति से बच सके और उन्हें अपनी उपज हेतु पानी की सुविधा प्राप्त होकर न्याय मिल सके।

(xxiv) Need to include Srikakulam in Andhra Pradesh in the list of smart cities

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I would like to draw the kind attention of the Government towards the accumulation of solid wastes, overflowing drains, stagnant water on streets and non-biodegradable items like plastic bottles, polythene covers and hospital waste causing environmental problems and outbreak of amoebiasis, gastroenteritis, malaria and typhoid in Srikakulam Municipality, Andhra Pradesh. Srikakulam Municipality have faced the drainage problem due to storage of water at the middle of the roads in the absence of underground drainage in Srikakulam Municipality, the sewage water flows in open canals, which even contain garbage wastes as people are used to throw all refuse into the canals. With the accumulation of silt, the canals overflow at the occurrence of even normal rainfall. As per the samples collected by the district headquarters hospital, some 7.42 per cent patients were suffering from typhoid, 66.2 per cent from amoebiasis, 16 per cent from gastroenteritis and 10.38 per cent from malaria due to the prevailing insanitary conditions in the town. I would like to inform you that the measures suggested by the committee constituted by the Supreme Court of India like ban on throwing waste on the streets, levying of administration charges from those who litter the streets, segregation of waste at source, sweeping the streets all the 365 days and creating awareness on public health are not being implemented properly in the Srikakulam Municipality. I urge upon the Central Government to make Srikakulam Municipality a smart city on the guidelines of Ministry of Urban Development, Government of India so that the living condition improves.

(xxv) Need to compensate Telangana for losses due to heavy rains during September, 2016

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Incessant and heavy rains in the month of september this year brought life to a standstill in most parts of Telangana and caused widespread damage to property, crops, highways, livestock etc. The Telangana Government has pegged the losses due to the calamity at Rs. 2740 crore. The Municipal department suffered financial losses to the tune of Rs. 848 crore, the agriculture department incurred Rs. 192.77 crore worth of losses, irrigation department sustained Rs. 112 crore losses and Panchayat Raj Department suffered losses worth Rs. 290 crore. The Chief Secretary has already presented the report to the Centre's assessing team about the losses caused to the State's exchequer.

I request the Centre to expedite the process of verification and examination of these losses and promptly compensate the state Government to help it tide over the crisis.

(xxvi) Need to set up Ekalavya Model Residential Schools in remaining four districts of Tripura

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Ekalavya Model Residential Schools (EMRS) funded by the Ministry of Tribal Affairs, have been found to be very useful for tribal students. Government of India is supposed to establish at least one such school in every tribal majority District in the country. Tripura is one of the predominantly tribal majority States in the country, having 8 (eight) Districts. Out of this 8 (eight) districts, only four are having EMRS. Remaining four Districts i,e. North Tripura, Dhalai, Sepoyjola and Gomati are yet to have EMRS. Ministry of Tribal Affairs may consider to set up EMRS in these remaining Districts on priority so that students of poor tribal families in these districts get benefitted.

(xxvii) Need to include crop loss due to spurious seed varieties and damage caused by wild animals in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to request the Government to cover the crop loss due to spurious seed varieties and damage by wild animals under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The scheme scores well over the previous schemes as the premium has been kept low, provides full coverage of insurance and covers post harvest losses as well. But the significant drawback of the scheme is that it does not provide any coverage against crop losses as a result of spurious seed varieties and crop damage by wild animals. We have witnesses the whitefly pest attack which got exacerbated because of inferior quality of seeds taking a heavy toll on the cotton crop in Northern India particularly in Haryana and Punjab last year. Therefore, I request the government to make necessary amendments in the newly introduced crop insurance scheme so as to ensure justifiable insurance for the crop losses due to wild animals and spurious seed varieties.

(xxviii) Need to release relief fund to Bihar for rehabilitation of people distressed due to loss of life and property caused by floods in the State.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अगस्त-सितम्बर, 2016 में गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिससे बिहार राज्य को काफी जान-माल एवं आर्थिक क्षति हुई है। गंगा इस वर्ष पूर्ण उफान पर थी और इससे नदी किनारे बसे शहर-गॉव और खेत-खलिहान को काफी नुकसान पहुॅचा। करीब 300 से अधिक लोगों की जाने गईं। वे डूब गये या पानी में बह गये पता नहीं चला। लहलहाती फसल पानी की चपेट में आकर नष्ट हो गई। लाखों घर पानी में बह गये। सड़कें, पुल-पुलिया और परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रेल की पटरियॉ भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। सबसे अधिक किसानों को हानि हुई, जिनकी फसलें नष्ट हो गईं। आपदा विभाग ने 22 सितम्बर, 2016 को ही 4,111.98 करोड़ रूपये की हुई हानि का विस्तृत ब्यौरा केन्द्र सरकार के पास भेज दिया। फिर भी पिछले लगभग दो महीनों में केन्द्रीय टीम बिहार आकर क्षति का आकलन नहीं कर सकी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में माननीय गृहमंत्री को पत्र भी भेजा। बाढ़ से हुई व्यापक क्षति के बारे में अवगत भी कराया। साथ ही 23 अगस्त, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तु-स्थिति की जानकारी दी। माननीय गृहमंत्री जी से भी मिले, किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में अपेक्षा के अनुरूप सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सर्वसम्मति से अनुमोदित बिहार विधान सभा का प्रस्ताव ''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा'' देने की मॉग को अनसुना कर और बाढ़ से इस वर्ष हुई भयंकर क्षति के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

अब केन्द्र सरकार वहॉ टीम भेजने की बात सोच रही है। कई बार तिथि निर्धारित कर रद्द भी कर चुकी है। इतने दिनों बाद जब किसान अपनी अगली फसलों की बुआई कर चुके हैं। घर की मरम्मत या बना रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल-पुलिया बनाये जा रहे हैं, फिर केन्द्रीय टीम के दौरे का क्या औचित्य रह जाता हैi अब ऐसी परिस्थिति में क्षति का आकलन करने में कठिनाई नहीं होगीi वैसे ही बिहार गरीब राज्यों की श्रेणी में निचले पायदान पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार दोहराते हैं कि बिहार का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, तो फिर क्या यही प्राथमिकता का पैमाना हैi अतः आग्रह है कि राज्य को क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार सहायता राशि के रूप में 4,111.98 करोड़ रूपये जल्द से जल्द निर्गत करे।

22.11.2016

(xxix) Need to provide reservation to Maratha community.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार (पटेल), राजस्थान में गुर्जर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में जाट लोग बीते बहुत दिनों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलित हैं। इसमें महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सब राज्यों में कभी न कभी आरक्षण जैसे मुद्दों पर हिंसक घटनाएं घटती रहती हैं और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में बीते दो महीनों से मराठा समाज ने आरक्षण की मुख्य मांग को लेकर लाखों की तादाद में विशाल रैलियां की है तथा युवा, युवती एवं वृद्ध सहित सभी वर्ग के लोग रास्ते पर उतर आये हैं। लेकिन प्रदेश में निकली इन विशाल रैलियों की एक खासियत भी थी कि ये रैलियां सेना की फौज की तरह अनुशासित एवं सभ्य थी। लेकिन इस तरह की घटनाओं से देश बेचैन है। आंदोलनकर्ताओं की मांग न्यायोचित है। इस आरक्षण आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण की मांग करने वाले ये सभी लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं एवं किसान हैं और देश को खड़ा करने में किसान का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इनकी संख्या भी अत्यधिक है। सबसे पहला कार्य इनके लिए जो हमें करना होगा वह इन पर जो वर्षों से कृषि ऋण का बोझ है उसको हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को स्वीकृति देनी होगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण हेतु फीस माफी या अनुदान की व्यवस्था, इसके साथ-साथ इनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण भी देना होगा। ये सभी चीजें सरकार को अतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। सातवें वेतन आयोग को सरकार ने अपनी स्वीकति दे दी है उससे कम से कम एक लाख करोड़ रूपयों का बोझ सरकारी खजाने पर हमेशा के लिए पड़ने वाला है। इस देश के अन्नदाता किसान को इस निर्णय से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसलिए सरकार को आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय लेने की आज नितांत आवश्यकता है।

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा क्यों कर रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब उसका निर्णय हो गया।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई नहीं बोलेगा ।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will not allow it; I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ज़ीरो आवर भी नहीं चाहेंगे।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 23rd November, 2016 at 11 a.m.

12.15 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 23, 2016/ Agrahayana 2, 1938 (Saka).